भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 57

22.07.2024 को उत्तर के लिए

कावेरी बेसिन में हरित क्षेत्रों में कमी

57. डॉ. शशि थरूर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत पांच दशकों के दौरान कावेरी बेसिन में हरित क्षेत्र में भारी कमी को उजागर करने वाली भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) की रिपोर्ट के बारे में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा दिए गए नोटिस का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रिपोर्ट में उजागर की गई संबंधित पर्यावरणीय प्रवृत्तियों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने कावेरी बेसिन में पर्यावरणीय दुरुपयोग को कम करने के लिए नीतिगत विकल्पों का व्यापक जोखिम-मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों पर कार्रवाई करने के लिए केरल राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) इस मंत्रालय को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए ओए संख्या 787/2023 के मामले में दिया गया नोटिस प्राप्त हुआ है और यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) एनजीटी ने पूर्वोक्त मामले में केरल सरकार को एक पक्षकार बनाया है।

****